वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का शिक्षा पर प्रभाव

डॉ0 विनय कुमार त्रिपाठी

प्राचार्य
श्री गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय
सुजानगंज जौनपुर

कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए क्योंकि महामारी के दौरान सभी बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसर, साधन या पहुंच नहीं थी। लाखों छात्रों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में अस्थायी तौर पर व्यवधान भर नहीं, बल्कि अचानक से इसका अंत होना था।

शिक्षा को तमाम सरकारों की पुनर्निर्माण योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए ताकि दुनिया भर में हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा सुलभ हो सके। लन्दन के एक रिपोर्ट में कहा कि सरकारों को कोविड–19 महामारी से हुए अभूतपूर्व व्यवधान के कारण बच्चों की शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए. ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट के साथ एक इंटरैक्टिव फीचर है जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा से जुड़ी आम बाधाओं के गहराने की पड़ताल की गई है।[1]

इनक्वालिटीज इन चिल्ड्रेन्स राइट टू एजुकेशन ड्यू टू द कोविड–19 पैन्डेमिक'') में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से कैसे बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए। क्योंकि महामारी के दौरान तमाम बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसर, साधन या पहुंच नहीं थी. ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा संबंधी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। अनेक सरकारों के पास ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए ऐसी नीतियां, संसाधन या बुनियादी ढांचा नहीं थे जिससे कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सके।[2]

ह्यूमन राइट्स वॉच की सीनियर एजुकेशन रिसर्चर एलिन मार्टिनेज ने कहा, ''महामारी के दौरान लाखों बच्चों के शिक्षा से वंचित होने के कारण, अब समय आ गया है कि बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण एवं मजबूत शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण कर शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ महामारी से पहले की स्थिति बहाल करना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उन खामियों को दूर करना होना चाहिए जिनके कारण लंबे समय से स्कूल के दरवाजे सभी बच्चों के लिए खुले नहीं हैं।

मई 2021 तक, 26 देशों में स्कूल पूरी तरह से बंद थे और 55 देशों में स्कूल केवल आंशिक रूप से या तो कुछ स्थानों में या केवल कुछ कक्षाओं के लिए खुले थे। यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर में स्कूल जाने वाले करीब 90 फीसदी बच्चों की शिक्षा महामारी में बाधित हुई है। यहां तक कि जो छात्र अपनी कक्षाओं में लौट आए हैं या लौट आएंगे, साक्ष्य बताते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक वे महामारी के दौरान पढ़ाई में हुए नुकसान के प्रभावों को महसूस करते रहेंगे। बहुत से बच्चों की पढ़ाई में क्षति पहले से मौजूद समस्याओं के कारण हुई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, कोविड–19 के प्रसार से पहले ही पांच में से एक बच्चा स्कूल से बाहर था। कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से खास तौर पर महामारी के पूर्व शिक्षा में भेदभाव और बहिष्करण का सामना करने वाले समूहों के छात्रों को नुकसान पहुंचा है। इन छात्रों में शामिल हैं, गरीबी में रहने वाले या उसकी दहलीज पर खड़े बच्चे, विकलांग बच्चे, किसी देश के नृजातीय और नस्लीय अल्पसंख्यक समूहों के बच्चे, लैंगिक असमानता वाले देशों की लड़कियां, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों या सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे, और विस्थापित, शरणार्थी, प्रवासी तथा शरण मांगने बच्चे।

कोविड के कारण बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसरों तक पहुंच नहीं थी। लाखों छात्रों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में अस्थायी तौर पर व्यवधान भर नहीं, बल्कि अचानक से इसका अंत होना था।

महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा संबंधी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। अनेक सरकारों के पास ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए ऐसी नीतियां, संसाधन या बुनियादी ढांचा नहीं थे जिससे कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सके।

महामारी के दौर में स्कूल सभी छात्रों को समान रूप से दूरस्थ शिक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसका कारण सरकारों की अपनी शिक्षा प्रणाली में भेदभाव और असमानताओं को दूर करने, या घरों में सस्ती, सुचारू बिजली जैसी बुनियादी सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने या सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी नाकामयाबी है। कम आय वाले परिवारों के बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई से बंचित होने के अधिक आसार थे क्योंकि वे पर्याप्त डिवाइस या इंटरनेट नहीं खरीद सकते थे। ऐतिहासिक रूप से कम संसाधनों वाले स्कूलों ने, जिनके छात्र पहले से ही शिक्षा संबंधी बड़ी बाधाओं का सामना कर रहे थे, वे डिजिटल सीमाबद्धताओं के समक्ष अपने छात्रों को पढ़ाने में विशेष कठिनाइयों का सामना किया। शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने में विफल रही है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र और शिक्षक इन तकनीकों का सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।

सरकारों और स्कूलों को इसका विश्लेषण करना चाहिए कि किसने स्कूल छोड़ा और कौन वापस आया और सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल वापसी कार्यक्रम पढ़ाई छोड़ने वाले सभी बच्चों की खोजबीन करे, साथ ही इसके लिए उन्हें वित्तीय और सामाजिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए. स्कूल वापसी कार्यक्रम अभियानों की पहुंच व्यापक होनी चाहिए और इसे उन तमाम बच्चों और युवाओं का स्वागत करना चाहिए जो स्कूलों के बंद होने के पहले से ही शिक्षा प्रणाली से बाहर थे। सभी सरकारों और उनकी मदद कर रहे दाताओं और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को समावेशी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ होना चाहिए। मजबूत प्रणाली के निर्माण के लिए जरूरी है कि पर्याप्त निवेश और संसाधनों का समान वितरण किया जाए, साथ ही भेदभावपूर्ण नीतियों और कार्यप्रणालियों को तुरंत हटाया जाए।

स्कूल बंद होने के दौरान, ज्यादातर देशों में, शिक्षा या तो ऑनलाइन या अन्य दूरस्थ तरीकों से प्रदान की गई, लेकिन इसकी सफलता और गुणवत्ता में भारी अंतर है। इंटरनेट तक पहुंच, कनेक्टिविटी, सुलभता, भौतिक तैयारी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और घर की परिस्थितियां समेत कई मुद्दों ने दूरस्थ शिक्षा की व्यवहार्यता को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया।

भारत में स्थित मुख्य रूप से अनाथ या गरीब घरों के बच्चों के एक स्कूल के एक शिक्षक ने कहाः "अगर माता–पिता शिक्षित हैं, तो वे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और दूरस्थ शिक्षा में मदद कर सकते हैं जैसा कि मेरे पति और मैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन बहुत से छात्रों के माता–पिता अशिक्षित या अनपढ़ होते हैं या उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं होता है। ऐसे छात्रों को नुकसान होगा और उनकी प्रगति धीमी होगी."

इस प्रकार हम सकते हैं कि भारतीय शिक्षा के साथ–साथ पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था इस वैश्विक महामारी के कारण अस्त व्यस्त हो गई है जिससे शिक्षण संस्थाओं के साथ–साथ छात्रों का अहित निहित है और यह नुकसान हम आजीवन पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस महामारी के माध्यम से हम अपने को स्वावलंबी एवं विषम परिस्थितियों में शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची :–

1–(लंदन, 17 मई, 2021) – ह्यूमन राइट्स वॉच

2– इनक्वालिटीज इन चिल्ड्रेन्स राइट टू एजुकेशन ड्यू टू द कोविड–19 पैन्डेमिक